(b) if so, what are their demands; and

(c) what action Government propose to take to mitigate the undue hardship caused to the litigants?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSMALIK): (a) Yes, Sir.

(b) The practising lawyers of Tis Hazari Courts are at present demanding enhancement of the original pecuniary jurisdiction of the District Courts.

(c) The matter is being currently examined by the Government of India.

संपर्क नहर प्रणाली पर प्रतिवेदन

1036. **श्रीमती कैलाशपति :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अपनी जांच तथा अध्ययन के आधार पर पांच संपर्क नहर प्रणालियों के संबंध में एक प्रतिवेदन सरकार को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन नदियों के नाम क्या हैं जिन पर ऐसी संपर्क नहरों के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार ने देश के कृषि विकास को ध्यान में रखते हुये, उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है : और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी योजना के कब तक तैयार होने जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने निम्नलिखित पांच जल अंतरण सम्पर्कों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है :-

1. महानदी – गोदावरी (डाउनलिसवरम) – पोलावरम ।

2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) ।

3. पार – तापी (दमनगंगा–तापी) ।

4. केरल के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां – चित्तार–वैगई

5. केन– बेतवा ।

इन रिपोर्टों पर संबंधित राज्य सरकारों की सहमति मिल जाने के बाद ही इन संपर्कों के लिये विस्तृत फ़ील्ड अन्वेषण शुरू किये जायेंगे ।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का दायित्व

1037. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985 में घोषित वस्त्र नीति के उपबंधों के अनुसार, नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की पूरी जिम्मेदारी हथकरघा उद्योग पर डाली जायेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय में हाल ही में परिवर्तन करके नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिए कुछ जिम्मेदारी पुनः कपड़ा मिलों पर डाल दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के परिणाम स्वरूप हथकरघा उद्योग को होने वाले घाटों को पूरा करने के लिए सरकार ने इस उद्योग को क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जाने की घोषणा की है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एन टी सी द्वारा सामना की जा रही कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कन्ट्रोल के कपड़े का समग्र उत्पादन हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित नहीं किया गया है । फिर भी हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है । वर्ष 1990-91 के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन लक्ष्य 600 मिलियन वर्ग मीटर है जब कि इसकी तुलना में वर्ष 1984-85 में यह 360 मिलियन वर्ग मीटर था ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना

1308. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश मे राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितनी धनराशि के खर्च किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन मिलों का आधुनिकीकरण हो जाने के बाद उन्हें होने वाले वार्षिक लाभों की बाबत अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार लगाये गये अनुमान की राशि कितनी है तथा इन मिलों के आधुनिकीकरण तथा अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली धनराशि के इन मिलों द्वारा अर्जित लाभ की राशि में से, कितने वर्षों में वसूल कर लिए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है । फिर भी सरकार एन टी सी की मिलों का आधुनिकीकरण क्रियान्वित नहीं करती । सरकार एन टी सी को मार्जिन धनराशि प्रदान करने के लिए बाजार व्यवस्था करती है ताकि वह अपनी आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सके ।

अभी तक वित्तीय संस्थानों ने 20 एन टी सी मिलों के लिए आधुनिकीकरण प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिन पर 90.87 करोड़ रु. व्यय होंगे । इसके अतिरिक्त एन टी सी ने वित्तीय संस्थानों के अनुमोदन के लिए 122.61 करोड़ रु. के परिव्यय वाली आधुनिकीकरण योजना भी प्रस्तुत की है ।

वित्तीय संस्थान आधुनिकीकरण प्रस्तावों की जांच करते हैं तथा उन्हें प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है जिन्हें अर्थक्षम पाया जाता है तथा जिनसे एक निर्धारित अवधि में मिलों द्वारा लाभ कमाने में सहायता मिलती है ।

Premises leased out to branches of Andhra Bank in Bombay

1039. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some branches of Andhra Bank in Bombay are still occupying the premises leased out to them even after the expiry of the lease period;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to renew the lease agreements with the lessors/landlords in accordance with the guidelines issued by Government to all the nationalised banks in this regard; and